

‘जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए सरकार को’

सेना का यह मत है, जिससे भारत की सरकार को अवगत कराया गया है

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 5 मई। पहलागम के घातक आतंकी हमले को दो सप्ताह हो गये। इस दौरान, देश की जनता का आक्रोश जहाँ दिनों-दिन बढ़ रहा है, वहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं तथा केन्द्र सरकार ने जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेने का फैसला किया है। बताया जाता है कि इसके बजाय, वे कश्मीर में आतंकवाद को प्रेरित-पोषित करने में पाकिस्तान की कथित लिप्तता से निबटने के लिए एक व्यापक और दीर्घकालिक रणनीति पर काम कर रहे हैं। इस हमले, जिसमें देशभर के कई निर्दोष पड़कित मारे गये, के बाद मोदी सरकार पर बदला लेने के लिए दबाव बढ़ता ही जा रहा है। सोलल मोडिया, टेलिविजन की बहसें तथा राजनैतिक विपक्ष, बार-बार एक ही बात कह रहे हैं-जल्दी और निर्णायक कार्यवाही करो। तथापि, उच्च स्तरीय सूत्रों के अनुसार, सरकार सभी विकल्पों का आकलन बड़ी सावधानी के साथ कर रही है तथा वह पूरी और सुस्पष्ट योजना के बिना कोई सीधी सैन्य कार्यवाही करने की जल्दबाजी में नहीं है। पिछले पूरे पखवाड़े में, शीर्ष-

- हालांकि, सोशल मीडिया, टेलिविज़न बहस व विपक्ष का पूरा दबाव है कि भारत को जल्दी ही मजबूती से पहलगांव के बदले की कार्यवाही करनी चाहिए।
- भारतीय थल, वायु व नौसेना अध्यक्ष इस बात पर लगभग एक मत हैं, भारत की कोई भी बदले की सैन्य कार्यवाही एक दीर्घकालीन रणनीति का हिस्सा होनी चाहिए, केवल जल्दबाजी में बदले की भावना से कार्यवाही नहीं होनी चाहिए।
- रिटायर्ड ले. जनरल, सर्वजीत सिंह दिल्ली का इस बारे में कहना है, कि, आक्रमण कब और कैसे करने का निर्णय, भावना या दबाव में नहीं लेना चाहिए।

स्तरीय सुरक्षा मीटिंग हुई। बताया जाता है कि थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना प्रमुखों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह तथा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सी सी एस) को संभावित सैन्य एवं रणनीतिक विकल्पों के बारे में जानकारी दे दी है। इन चर्चाओं के जानकारी सूत्रों का कहना है कि सैन्य नेतृत्व में इस बात, पर व्यापक सहमति है कि कोई भी कार्यवाही, तालाकालिक एवं अल्पकालीन बदले के बजाय, किसी दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा होनी चाहिए।

एक वरिष्ठ रक्षा-अधिकारी ने, उसका नाम न बताये जाने के अनुरोध के साथ, बताया, “यह तीनों सेनाओं का सर्वसम्मत विचार है कि आतंकी इन्फ्रास्ट्रक्चर को तोड़ने तथा गहरी जड़ें जमा चुके विद्रोही नेटवर्क, जो कथित रूप से पाकिस्तानी सेना तथा उसकी खुफिया एजेंसी आई एस आई द्वारा रचित एवं नियंत्रित है, को प्रभावहीन करने के लिए स्थायी एवं दीर्घकालिक प्रयासों की जरूरत है, सिर्फ एक एक्शन की नहीं।” इन्हीं विचारों को दोहराते हुए, पुराने युद्ध-विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल

(सेवानिवृत्त) सरबजीत सिंह दिल्ली जोर देते हुए कहा कि सैन्य कार्यवाही समयबद्धता एवं राजनैतिक अत्यावश्यकता से निर्देशित नहीं हो सकती। दिल्ली ने कहा, “जमीनी हकीकत के आकलन का काम सशस्त्र सेनाएं करती हैं तथा कोई भी मिशन शुरू करने से पहले, सेनाएं सभी भू-रणनीतिक तत्वों, भू भाग (टैरेन) तथा सम्पूर्ण सैन्य भूमिका को ध्यान में रखती हैं, उन पर विचार करती हैं। -- हमले का आव्हान भावना या दबाव से निर्देशित एवं नियंत्रित नहीं हो सकता।”

रविवार को पत्रकारों से बात करते समय, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह इसी विचार के समर्थन में दिखाई दिया। सिंह ने कहा, “सरकार सभी विकल्पों को खंगाल रही है। हम भारत की जनता की भावनाओं से पूरी तरह परिचित हैं। राष्ट्र हमारे बहादुर सैनिकों के बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। लेकिन इसके साथ ही, हम कोई भी कार्यवाही इस तरह करेंगे कि वह रणनीतिक तथा प्रभावही हो।” भारतीय नेतृत्व की यह सजग, किन्तु दृढ़ सोच भाववेशपूर्ण कार्यवाही की बजाय, दीर्घकालिक रोग निवारण को प्राथमिक देने का संकेत देती दिखाई दे (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एस.आई.भर्ती : 15 तक सरकार निर्णय ले, वरना कोर्ट तय करेगी

जयपुर, 5 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में भर्ती के अस्तित्व को लेकर राज्य सरकार को अपना रुख स्पष्ट करने के लिए अंतिम मौका देते हुए मामले की सुनवाई 15 मई को रखी है। अदालत ने कहा कि यदि राज्य सरकार ने कोई फैसला नहीं दिया तो अदालत पक्षकारों को सुनकर अपने स्तर पर निर्णय देगी। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की

- जस्टिस समीर जैन ने पेपर लीक से हुई भर्ती पर राज्य सरकार को रुख स्पष्ट करने का अन्तिम मौका दिया।

ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि भर्ती पर निर्णय करने के संबंध में किन्हीं कारणों से मीटिंग नहीं हो पाई है। अब सब कमेटी की यह मीटिंग 13 मई को होनी है। ऐसे में राज्य सरकार को अपना रुख स्पष्ट करने के लिए समय दिया जाए वहीं ईडी की ओर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘राजनीतिक आधार पर सरकारी वकीलों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए’

जयपुर, 5 मई। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता और सरकारी वकील सहित लोक अभियोजकों की नियुक्ति में योग्यता की अनदेखी कर उनकी राजनीतिक आधार पर नियुक्ति के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका पेश की गई है। मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस मुकेश राजपुरोहित की खंडपीठ ने पूनम चंद भंडारी की जनहित याचिका पर राज्य सरकार को इस मुद्दे पर पूर्व में निस्तारित अन्य याचिका में दिए आदेशों

- हाईकोर्ट में पेश जनहित याचिका में पूर्व में दिये गये आदेशों की प्रति पेश करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिये गये।

की कॉपी पेश करने को कहा है। जनहित याचिका में अधिवक्ता टीएस शर्मा ने कहा कि बीते कई सालों से राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट सहित अन्य अदालतों में सरकार का पक्ष रखने के लिए राजनीतिक विचारधारा वाले वकीलों को नियुक्त किया जाता है। इनमें से कई वकील ऐसे नियुक्ति हो जाते हैं, जो वास्तव में उस पद के योग्य ही नहीं होते हैं। जिसके चलते न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। हाईकोर्ट पूर्व में इस संबंध में गंभीर टिप्पणी भी कर चुका है। याचिका में कहा गया कि यदि वकीलों की नियुक्ति उनकी योग्यता को ध्यान में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राज्य भंडारण निगम ने श्री शुभम लॉजिस्टिक और सहायक कंपनी के खिलाफ चल रहे मामले में “सोल आरबिट्रेटर” को हटाने की याचिका दायर की

राज्य भंडारण निगम का इन दोनों कंपनियों के खिलाफ 202 करोड़ रुपये के दावे का मामला “आरबिट्रेशन” में है

- यादवेंद्र शर्मा -

- सोल आरबिट्रेटर को हटाने के मामले में दायर याचिका में राज्य भंडारण निगम का कहना है कि सेवा निवृत्त पूर्व न्यायाधीश के.एस.सिंह को एक ही वर्ष में, एक ही मामले से जुड़ी पार्टियों के बीच सात मामलों में “सोल आरबिट्रेटर” नियुक्त किया गया।
- जबकि नीति यह है कि दो कंपनियों या दो व्यक्तियों के बीच चल रहे सिर्फ दो मामलों में ही एक व्यक्ति विशेष को सोल आरबिट्रेटर बनाया जा सकता है।
- उल्लेखनीय है कि के.एस. राठौड़ ने मध्यस्थता के लिए नियुक्त होने से पूर्व दिये गये “डक्लेरेशन” (कानूनी घोषणा) में भी इस तथ्य को उजागर नहीं किया।

नियुक्त किये जा चुके हैं, जबकि नीति और नियम कहता है कि एक व्यक्ति विशेष को दो कंपनियों या व्यक्तियों के बीच चल रहे सिर्फ “दो” मामलों में ही

सोल आरबिट्रेटर नियुक्त किया जा सकता है।

भण्डारण निगम का कहना है कि नीति और नियम के विरुद्ध नियुक्त किये

गये “सोल आरबिट्रेटर” को हटाने के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने ऐतिहासिक फैसला दिया है, और यह फैसला मध्यस्थता कर रहे व्यक्ति विशेष की योग्यता और इसकी प्रक्रिया व संचालन निष्पक्ष रखने की दृष्टि से दिया गया है।

जैसा कि विदित है कि पिछली गहलोट सरकार के कार्यकाल के दौरान राजस्थान राज्य भण्डारण निगम और श्री शुभम लॉजिस्टिक तथा उसकी सहायक कंपनी ओरिगो कर्मांडिटोज इण्डिया के बीच कृषि उपज के भण्डारण के संबंध में हुए अनुबंधन को लेकर भारी भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर पिछले एक वर्ष से खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं। इस मामले में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री भजन लाल को शिकायती पत्र (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्रदेश में लू से निपटने का एक्शन प्लान दें

जयपुर, 5 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रदेश में लू के हालातों से निपटने के लिए बनाए गए एक्शन प्लान की जानकारी देने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में केन्द्र सरकार सहित अन्य से जवाब पेश करने को कहा है। चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस मुकेश राजपुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश

- हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से एक्शन प्लान की जानकारी देने को कहा।

प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए। वहीं अदालत ने समान बिंदु पर एकलपीठ की ओर से गत दिनों लिए प्रसंज्ञान को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि जब मामले में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेकर मामला खंडपीठ में सुनवाई के लिए भेजा गया है तो उस विषय पर पुनः स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेने का कोई औचित्य नहीं है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

अज्ञान जैसा शत्रु दूसरा नहीं। –चाणक्य

विपक्ष सरकार के साथ है, लेकिन सरकार कहां है?



डॉ. रमेश बैरवा

5 मई को विश्वविख्यात क्रांतिकारी चिंतक कार्ल मार्क्स का जन्मदिन मनाया गया। ऐसे मार्क्स जिन्हें बीबीसी ने सहस्त्राब्दी का सबसे प्रभावशाली दार्शनिक माना है। जिन्होंने साम्यवाद का आदर्श दुनिया के सामने रखा। ऐसा साम्यवाद जिसमें निजी संपत्ति के पूर्ण उन्मूलन के साथ समाज वर्गविहीन, राज्यविहीन हो जाता है। जहां विषमता, भेदभाव, बेरोजगारी, जाति, जेंडर, धर्म, रंग-रूप, भाषा, राष्ट्र के आधार पर लोगों में वैमनस्य नहीं रहता। हर प्रकार के शोषण,अन्याय से समाज मुक्त हो जाता है। मजदूर, मेहनतकशों के शोषण और प्राकृतिक संसाधनों के बेरहमी से दोहन पर आधारित मुनाफे

से संचालित पूंजीवादी समाज के स्थान पर साम्यवादी समाज की स्थापना होगी जो “एक ऐसा संघ होगा, जिसमें प्रत्येक का स्वतंत्र विकास सभी के स्वतंत्र विकास की शर्त होगी।”

ऐसे कार्ल मार्क्स का जन्मदिवस है जिन्होंने सबसे पहले मानव समाज के विकास के नियमों की वैज्ञानिक व्याख्या की। द्वंदात्मक भौतिकवाद का दर्शन दिया जिसके आधार पर इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की। वैज्ञानिक समाजवाद के प्रवर्तक है कार्ल मार्क्स। मार्क्स ने पूंजीवादी समाज में अंतर्निहित मानव शोषण एवं व्यवस्था के संकेत के बारे में वैज्ञानिक विश्लेषण दिया। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। पूंजीवादी समाज में अंतर्निहित मानव अलगाव के बारे में बताया। पूंजीवाद के साम्राज्यवादी स्वरूप के बारे में भी बताया। मार्क्स ने यह भी बताया कि पूंजीवादी आर्थिक शोषण को कायम रखने एवं इसको बढ़ाने के लिए कैसे सामाजिक भेदभाव का उपयोग किया जाता है। कैसे महिलाओं का शोषण बरकरार रखा जाता है। कैसे जाति, रंगभेद, राष्ट्रवाद का इस्तेमाल मेहनतकश तबके के आर्थिक शोषण को

कायम रखने के लिए किया जाता है। कार्ल मार्क्स का जन्म प्रशिया के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में 5 मई, 1८18 को हुआ था। मार्क्स के पिता एक वकील थे एवं उनकी प्रारंभिक शिक्षा एक स्थानीय स्कूल जिमनेजियम में पूरी हुई। बोन विश्वविद्यालय से उन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात् बर्लिन विश्वविद्यालय से दर्शन एवं इतिहास का अध्ययन किया। जेना विश्वविद्यालय से उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। कार्ल मार्क्स हीगेल के विचारों से भी बहुत प्रभावित थे। जर्मनी में जन्मे लेकिन अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण अपनी मृत्यु तक निर्वासित, तकलीफों का जीवन जीने वाले ऐसे महान अर्थशास्त्री मार्क्स का जन्मदिन है, जिन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था की कार्यप्रणाली के सबसे बेहतरीन तथ्यपरक, वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए विश्व प्रसिद्ध पुस्तक ‘दास कैपिटल’ की रचना की थी। मार्क्स ने अपने विश्लेषण में बहुत सटीक तरीके से समझाया है कि समाज में असमानता व्यक्ति को लालच के कारण नहीं जैसा कि अनेक आदर्शवादी, धार्मिक विद्वान मानते हैं, बल्कि स्वयं इस पूंजीवादी उत्पादन की

प्रक्रिया–अतिरिक्त मूल्य में ही निहित है। पूंजीवाद मूलतः शोषण और अन्याय पर आधारित व्यवस्था है जिसे उखाड़ फेंकने के लिए इसने अपने विरोधी सर्वहारा वर्ग को पैदा कर लिया है। मार्क्स ने लिखा है कि “मजदूर वर्ग द्वारा क्रांति में पहला कदम लोकतंत्र की लड़ाई जीतने के लिए सर्वहारा वर्ग को शासक वर्ग के पद पर उठाना है।” ऐसे कार्ल मार्क्स का जन्मदिन है आज जिनका मानना था कि “कोई भी राष्ट्र स्वतंत्र नहीं हो सकता यदि वह दूसरे राष्ट्रों का शोषण करता है।” मार्क्स ने पूंजीवाद की वैश्वीकरण की प्रक्रिया के बारे में 1८48 की रचना ‘कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो’ में ही बता दी थी।

मार्क्स लिंग समानता के प्रबल पक्षधर थे। उनका कहना था कि कोई भी व्यक्ति जो इतिहास की थोड़ी भी जानकारी रखता है, वह यह जानता है कि महान सामाजिक बदलाव बिना महिलाओं का उथ्थान किये असंभव है। महिलाओं की सामाजिक स्थिति को देखकर किसी समाज की सामाजिक प्रगति मापी जा सकती है। 1८4८ में ही मार्क्स के विचार इतने दूरदर्श थे,वे चाहते थे कि “सरकारी स्कूलों में सभी

—डॉ. रमेश बैरवा, राज. विज्ञान के प्रोफेसर हैं।

शादियों में फीकी पड़ने लगी बैंड–बाजे की गूंज

डीडवाना, (निसं)। शादी–विवाह का नाम आते ही जेहन में शहनाई की गूंज और बैंड की मधुर धुन का ही ख्याल आता है। शादी जैसे खुशी की रौनक बैंड–बाजा ही बढ़ाता है। कुछ सालों पहले तक हर बारात में बैंड की धुनें ही गूंजती थी। धार्मिक आयोजनों और उत्सवों में भी बैंड–बाजों का विशेष महत्व था, मगर बदलते दौर में बैंड–बाजों की धुन अब गुमनामी के अंधेरे में खोती जा रही है।

बैंड वादक सिराज और गुलाम रसूल बताते हैं कि आधुनिक डीजे के चलन में आने के बाद बैंड का चलन अब कम होने लगा है। जिसका सीधा असर बैंड व्यवसाय से जुड़े लोगों और उनके परिवारों पर पड़ने लगा है और वे बेरोजगारी का दर्श झेलने को मजबूर हैं। एक समय था जब शादी के मौके पर बैंड बाजे की गूंज शहनाई की मधुर पहले से लाइन लगानी पड़ती थी। बैंड वालों के पास इतना काम होता था कि उन्हें दिनभर में कई कई शिफ्टों में काम करना पड़ता था। शादी–विवाह के अनेक उत्सव में एक उत्सव बारात में



बदलते दौर में बैंड व्यवसायी काम नहीं मिलने से बेरोजगारी का दर्श झेलने को मजबूर हैं।

बैंड भी होता था। जब कभी बैंड की आवाज आती थी तो सहज ही लोग यह अनुमान लगाते थे कि आसपास शादी समारोह का आयोजन चल रहा है। बैंड में गूंजती शहनाई की मधुर आवाज और बैंड का शालीन संगीत मन को सुकून देता था। बैंड पर आवाज आती अपने आप झुमने नाचने लगते थे। कुछ सालों पहले तक हर शादी में बैंड की धुनें ही गूंजती थी।

रही है और आधुनिक डीजे के चलन में आने के बाद अब बैंड–बाजा संचालकों का कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, जिससे इस परंपरा और रोजगार दोनों पर संकट उत्पन्न होने लगा है। बदलते वक्त के साथ शадियों में बैंड बाजे की गूंज अब कम सुनाई देने लगी है।

अब बैंड के स्थान पर डीजे का चलन तेजी से बढ़ने लगा है। हालात

मार्क्सवाद की अन्तर्राष्ट्रीयता



रामनिवास बैरवा

कार्ल मार्क्स के समय पूंजीवाद की स्थिति एकाधिकार–मोनोपोली तथा कर्तलों के निर्माण में अभिव्यक्त होती थी। तब उपनिवेशों के लिए पूंजीवादी देशों में संघर्ष होते थे, लंबे समय तक चलने वाले युद्ध होते थे। आज पूंजीवाद अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के माध्यम से अपनी साम्राज्यवादी गतिविधियों को पूरा करता है। यह दुनिया का अन्तर्राष्ट्रीयकरण है। इस अन्तर्राष्ट्रीयकरण के संबंध में मार्क्स के अर्थव्यवस्था, राजनीति तथा समाज व्यवस्था के संबंध में वे निष्कर्ष हैं जो स्थानीय, राष्ट्रीय विशेषताओं को संरक्षित रखते हुए उन्हें उनके अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप में अभिव्यक्त करते हैं।

कार्ल मार्क्स मानव इतिहास के पहले ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने दर्शन शास्त्र के परम्परागत विषय –आत्मा–परमात्मा और धर्म से अलग हटकर समाज के ऐतिहासिक एवं भौतिक तथ्यों को केन्द्र बनाकर दर्शन शास्त्र को नया मोड़ दिया है। उन्होंने पहली बार तीन अलग–अलग एकांतिक बनाकर रखी गयी व्यवस्थाओं के अन्तर्संबंधों को स्थापित किया। ऐसा करने उन्होंने मानव–समाज के भूतकाल और वर्तमान की व्याख्या करके मानव–समाज के भविष्य की व्यवस्था की रूपरेखा प्रस्तुत की है, जिसे अन्तिम रूप में साम्यवाद या “कम्युनिज्म” नाम दिया है। उस समय और वर्तमान समय में भी देशों और राष्ट्रों की अलग–अलग व्यवस्थाओं को कम्युनिज्म का पर्याप्त बिंदु नहीं बनाकर अन्तर्राष्ट्रीयता के स्वरूप को प्रतिपादित किया था।

इसका आधार है–“दुनिया के मजदूरों, एक हों।” जब “दुनिया के मजदूरों, एक हों” का नारा दिया गया था तब इस नारे का अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप ही दिखाई देता है। आज हम देखते हैं कि पूरे विश्व की व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था बन चुकी है। रोलोबलाइजेशन के दौर में मुद्रा व्यापार और उत्पादनों का अन्तर्राष्ट्रीयकरण हुआ है। पूंजीवाद

की परम्परागत उत्पादन व्यवस्था एकाधिकार और कार्टेल व्यवस्था अब वेमानी हो गई है। छोटे–बड़े सभी ब्रांडों का उत्पादन पहले की तरह एक ही देश में, एक ही जगह पर नहीं किया जा रहा है बल्कि फ्रेंचाइजी और कॉपीराइट के उपयोग के आधार पर किया जा रहा है जो एक ही देश में सीमित नहीं है बल्कि एक से अधिक देशों में उनकी उत्पादन प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। इससे कोई भी उत्पादन एक देशीय न होकर अन्तर्राष्ट्रीय हो गया है।

सामाजिक संरचना में सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि कुछेक बड़े पूंजीपतियों को छोड़कर लगभग पूरी दुनिया की पूरी मानव जाति अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए वेतन के लिए काम करते हैं। यह भी एक स्थापित सत्य है कि मानवसमाज का प्रत्येक सदस्य जीवनयापन के लिए सामाजिक सुरक्षा का कवच चाहता है और वह सामाजिक सुरक्षा शिक्षा–चिकित्सा के अलावा जीवन–यापन के लिए नियमित रोजगार और उसके बदले में मिलने वाले वेतन में ही निहित है अतः पूरी दुनिया में सभी वेतन के लिए काम करने वाले, भ्रम करने वाले वकर्स ही हैं, श्रमिक ही हैं, मजदूर ही हैं। अतः कार्ल मार्क्स का आह्वान कि

“दुनिया के मजदूरों, एक हों” नयी सामाजिकता क ताने–बाने का अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप है। देशों की सीमाएं पूंजीवादी शासन व्यवस्था वाले देशों की हैं–मजदूरों–श्रमिकों की शासन व्यवस्था के लिए नहीं है। 1९17 में सोवियत क्रान्ति के बाद दुनिया के ऐसे देश जो किसी पूंजीवादी यूरोपीय देश के उपनिवेश नहीं थे, उनमें समाजवादी, कम्युनिस्ट क्रान्तियों का दौर आया था–लेकिन जो किसी यूरोपीय पूंजीवादी देश के उपनिवेश थे उनमें समाजवादी आंदोलन हो रहे थे लेकिन उपनिवेशवादी देशों के कम्युनिस्ट–विरोधी, समाजवादी विरोधी कारवाइयों, नीतियों के चलते उनमें समाजवादी क्रान्तियां तो सफल नहीं हो सकी, अपितु उनमें सत्ता के लिए संघर्ष निरन्तर चलते रहे। चीन, वियतनाम, कम्यूनिया, कोरिया, तुर्की, यमन, दक्षिण अमरीकी देश समाजवाद के लिए ऐसे संघर्षों के उदाहरण हैं।

भारत भी मार्क्सवादी समाजवाद के सैद्धांतिक एवं राजनीतिक प्रभाव से मुक्त नहीं है। जब दक्षिणपंथ की बात सामने आती है तो वामपंथ अपने आप ही राजनीतिक और सामाजिक सत्य के रूप में उभर कर सामने आता है। यही

कारण है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था दक्षिणपंथ और वामपंथ के बीच हिचकोले ले रही है। दक्षिणपंथ का उभार वामपंथ की आक्रामकता का कारण है तथा दक्षिणपंथ की पराजय वामपंथ की विजय तो नहीं कही जा सकती लेकिन सामाजिक संरचना के अनुसार राजनीतिक संतुलन का प्रयास है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, आस्ट्रेलिया, श्रीलंका आदि दक्षिणपंथ पर वामपंथ को एक अंकुश के रूप में देखा जा सकता है। दक्षिणपंथ की विजय अन्ततः तानाशाही को जन्म देती है और उस तानाशाही पर वामपंथ ही पूर्ण विजय प्राप्त कर सकता है, जैसे हिटलर पर सोवियत संघ की सेनओं ने विजय प्राप्त की थी। अगले सलाह रूस में उसी का 8०वां विजय दिवस मनेने की तैयारी है जिसमें भारत को भी आमंत्रित किया गया है। वामपंथ, कम्युनिज्म या समाजवाद कार्ल मार्क्स के निष्कर्षों की राजनीतिक व्यवस्था का अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप ही थे जो अन्ततः मानवजाति की स्वतंत्रता, मानवजाति की मुक्ति का मार्ग बनने का रास्ता दिखता है।

रामनिवास बैरवा
पूर्व क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के उत्थान के लिए कार्य कर रही राज्य सरकार : भजनलाल शर्मा

वडोदरा/जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विश्वभर में राजस्थान के प्रवासी प्रदेश का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। प्रवासी राजस्थानी अपनी कर्मभूमि के साथ-साथ मातृभूमि से भी जुड़े रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे राजस्थान के प्रवासी विश्वभर में चिकित्सा, शिक्षा, पेयजल सहित विभिन्न सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों से आह्वान किया कि 'आपणो अग्रणी राजस्थान' के संकल्प को पूरा करने में अपना अहम योगदान दें। शर्मा सोमवार को गुजरात के वडोदरा में राजस्थानी समाज द्वारा आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान शक्ति और भक्ति की धरती है। इस भूमि पर महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल, त्याग और तप की पर्याय पन्नाधाय, भक्ति की मूर्ति मीराबाई और पर्यावरण संरक्षिका मां अमृता देवी जैसी महान विपुलियों ने जन्म लिया था। इन सभी के महान कार्यों से आज तक हम सभी प्रेरणा ले रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार के 'कर्मभूमि से मातृभूमि' अभियान के तहत भामाशाहों और प्रवासी भाई-बहनों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। इसके तहत राज्य में लगभग 4.5 हजार जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को गुजरात के वडोदरा में राजस्थानी समाज की ओर से आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित किया।

अभियान वर्षा जल की एक-एक बूंद को सहेजकर जल उपलब्धता बढ़ाने तथा भूजल स्तर को बढ़ाने में भी मददगार बनेगा। शर्मा ने कहा कि प्रदेश की पानी की जरूरत को प्राथमिकता देते हुए रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, देवास परियोजना सहित अन्य जल परियोजनाओं को पूरा

किया जा रहा है। शर्मा ने कहा कि गुजरात तथा राजस्थान दोनों राज्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। गुजरात की धरती पर महात्मा गांधी तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुष पैदा हुए, जिन्होंने देश की एकता और अखण्डता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान के

औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए पिछले साल दिसंबर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि इस समिट में लगभग 37 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 3 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग की जा चुकी

- 'विश्वभर में प्रवासी राजस्थानियों ने प्रदेश को किया गौरवान्वित'
- "‘आपणो अग्रणी राजस्थान’ की संकल्प सिद्धि में प्रवासी राजस्थानी निभाएं अपनी भूमिका

है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन को आधार मानकर राज्य सरकार गरीब, युवा, महिला और किसानों का कल्याण सुनिश्चित कर रही है। शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में पेंशनरी की घटनाओं के कारण युवाओं के साथ विश्वासघात हुआ। हमारी सरकार भर्ती परीक्षाओं का आयोजन पूर्ण पारदर्शिता के साथ करवाने के साथ ही, युवाओं को समय पर रोजगार उपलब्ध करवा रही है। हम 5 वर्ष में युवाओं को 4 लाख सरकारी नौकरियों के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं तथा हमारी सरकार में एक भी पेंशनरी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पं. दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के लक्ष्य के साथ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के उत्थान के लिए कार्य कर रही है तथा हम संकल्प पत्र के प्रत्येक वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

मुख्यमंत्री ने की जनसुनवाई

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर नियमित जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने आमजन की प्रत्येक समस्या को सुना और अधिकारियों को इनके शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अपनी जवाबदेहीता सुनिश्चित करते हुए आमजन की परिवेदनाओं के त्वरित निराकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसुनवाई में आए प्रत्येक फरियादी को उसकी समस्या के निराकरण के लिए चल रही प्रक्रिया के बारे में नियमित रूप से अवगत कराया जाए। जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो तथा आमजन को राहत मिले।

गहलोत, बाड़ाबंदी व प्रशिक्षण शिविर में नहीं कर पा रहे अंतर : राजेंद्र राठौड़



भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेसवाता के दौरान मंच पर वरिष्ठ नेता राजेन्द्र राठौड़, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, प्रदेश मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ और प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज उपस्थित रहे।

- 'भाजपा के प्रशिक्षण शिविरों में विशेषज्ञों द्वारा गुड गवर्नेस, शुचिता की राजनीति और नीतिगत निर्णयों पर आयोजित होते हैं सत्र'

सरकार है, वहां प्रशिक्षण शिविर चलते रहते हैं। ऐसे में गहलोत द्वारा मौज-मस्ती जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना सरासर गलत है। भजनलाल सरकार लगातार जनहित में नीतिगत फैसले कर रही है। फिर चाहे बिजली की समुचित व्यवस्था हो या फिर पानी की व्यवस्था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अल्प कार्यकाल में इस बार भीषण गर्मी के दौर में भी ना तो बिजली कटौति की जा रही है और ना ही पानी की समस्या आ रही है। यह सब हो पाया है भजनलाल सरकार की नीतियों के चलते। उन्होंने कहा कि मौज-मस्ती के बारे में राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहिए, इसके राजकुमार हर तीसरे माह में मौज मस्ती करने के लिए विदेश भ्रमण

पर जाते हैं और विदेश में जाकर भारत के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करते हैं। भाजपा के प्रशिक्षण में अलग-अलग क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा गुड गवर्नेस के लिए और पारदर्शी शुचिता के साथ तथा नीतिगत निर्णय कैसे करें, किस प्रकार से जनप्रतिनिधि का आचरण हो, इस पर विभिन्न सत्रों में विचार-विमर्श होता है। कांग्रेस में प्रशिक्षण के नाम पर बाड़ाबंदी होती थी, केवल विमान यात्रा पर 3 करोड़ रूपए खर्च कर दिए जाते थे।

प्रेसवाता के दौरान मंच पर पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, भाजपा प्रदेश मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज उपस्थित रहे।

सर्व समाज के समूह विवाह में हुआ 54 जोड़ों का पाणिग्रहण संस्कार

जयपुर। सेवा भारती समिति की ओर से जानकी नवमी पर सोमवार को अम्बावाड़ी स्थित उच्च माध्यमिक बालिका आदर्श विद्या मंदिर में सर्वजातीय चतुर्दशम सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ। घर जैसे माहौल में एक ही मंडप में सोहह समाजों के 54 जोड़ों ने एक दूसरे को जीवनसाथी के रूप में स्वीकार किया। इनमें दस अंतर्जातीय जोड़े भी थे। एक वधू के माता-पिता दोनों ही नहीं थे। उनके विवाह का संपूर्ण दायित्व सेवा भारती ने निभाया। पंडितों ने वैदिक विधि से पाणिग्रहण संस्कार संपन्न करवाया। सेवा भारती के सदस्य ऐसे उत्साहित थे जैसे कि घर में विवाह हो रहा हो। सेवा भारती की महिलाएं एक ही रंग की साड़ी पहने नजर आईं और फेरों से पूर्व की रस्में करवाईं। सोलह श्रृंगार कर बरी के वेश में दुल्हनों ने अपने-अपने दूल्हे राजा के संग फेरे लिए।

इस दौरान सामाजिक समरसता की मिसाल देखने को मिली। गालसर बालाजी मंदिर के विष्णु पुजारी, सायनी चेतना केन्द्र मुरलीपुरा के मनु महाराज, महंत हरिशंकरदास वेदवती, अकिंचन महाराज सहित अनेक संतों-महंतों ने दलित दूल्हों के पैर धोए। भावपूर्ण दृश्य देखकर कर-वधु के परिवर्जनों की आंखें सजल हो उठीं। इससे पूर्व गाजेबाजे और लवाजमे के साथ विद्याधर महादेव मंदिर से बारात रवाना हुई। सभी 54 दूल्हे राजधज कर अलग-अलग घोड़ी पर बैठ कर विवाह स्थल पहुंचे और



सेवा भारती समिति की ओर से जानकी नवमी पर सोमवार को अम्बावाड़ी स्थित उच्च माध्यमिक बालिका आदर्श विद्या मंदिर में सर्वजातीय चतुर्दशम सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ।

तोरण मारा। तोरण की रस्म के बाद स्टेज पर वरमाला कराई गई। समिति की ओर से दूल्हा-दुल्हन को अपने जीवन की नई शुरुआत करने के लिए अनेक सामान उपहार स्वरूप दिए गए। इसमें सोने-चांदी के आभूषणबैड, अलमारी, पंखा, सिलाई मशीन, बक्सा, बर्तन, कपड़े सहित करीब दो दर्जन आयटम थे। सीतारामजी तस्वीर, तुलसी का पौधा, तुलसी माला,

पुस्तक भी उपहार स्वरूप दी गई। इतना अधिक सामान के आगे लोडिंग वाहन भी छोटा पड़ गया। आनन फानन में बड़े लोडिंग वाहन मंगवाने पड़े। खोजी द्वारचार्य रामरिछपाल दास महाराज, नारायण धाम के रामरतन दास महाराज, सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर के महंत अवधेशाचार्य, अकिंचन महाराज, मोतीदुर्गा गणेश मंदिर के महंत पं. कैलाश शर्मा, खोले के हनुमान मंदिर

के महामंत्री बृजमोहन शर्मा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निंबाराम, प्रांत प्रचारक बाबूलाल, मूलचंद सोनी, शिव लहरी , विधायक बालमुकुंदाचार्य सहित अनेक विशिष्टजनों ने नव विवाहित जोड़ों को सुखद दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद प्रदान किया। समिति ने सभी को शॉल ओढ़ाकर, नारियल तथा माला पहनाकर सम्मान किया।

वनरक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में 18 आरोपियों का आरोप पत्र दाखिल

जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार शुदा अग्रहार आरोपियों का एडीजे न्यायालय बांसवाड़ा में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल कर दिया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एटीएस और एसओजी वीके सिंह ने बताया कि वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार शुदा छान पारगी निवासी सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा, सूर्यकान्ता निवासी बांसवाड़ा हाल वनरक्षक बांसवाड़ा, फिरोज निनामा निवासी सज्जनगढ़ जिला बासवाडा, समुएल निनामा निवासी भूगड़ा जिला बांसवाड़ा हाल वनरक्षक बांसवाड़ा, प्रताप बामनिया निवासी सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा, हीराराम सारण उर्फ हरीश निवासी गुडामलानी जिला बाड़मेर हाल तृतीय श्रेणी अध्यापक उदयपुर ,रमेश कुमार जाणी निवासी भीनमाल जिला जालौर ,शारदा निवासी बागपुरा जिला उदयपुर, कमलेश कुमार निवासी करडा जिला जालौर हाल कांस्टेबल उदयपुर, रेशमी निवासी करडा जिला जालौर, सांखलाराम जाट निवासी गुडामलानी जिला बाड़मेर, कंवराराम निवासी गुडामलानी जिला बाड़मेर, भीयराम निवासी गुडामलानी जिला बाड़मेर हाल कांस्टेबल उदयपुर, देवाराम निवासी करडा जिला जालौर हाल कांस्टेबल उदयपुर, सीमा कुमारी निवासी सिवाना जिला बाड़मेर हाल वनरक्षक रंज बालोतरा, टिमो निवासी बीजड़ा जिला बाड़मेर हाल वनरक्षक रंज चौधटन, कंवराराम चौधरी निवासी सिणधरी जिला

बालोतरा हाल स्टेशन मास्टर पालनपुर गुजरात और लिखमराम निवासी बिजराड जिला बाड़मेर हाल पुलिस कांस्टेबल ट्रेफिक पुलिस चौहटन के खिलाफ एडीजे न्यायालय बांसवाड़ा में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया है। एडीजी एटीएस और एसओजी वीके

सिंह ने बताया कि 30 जून 2024 को पुलिस थाना राजतलाब जिला बांसवाड़ा की ओर से 13 नवम्बर 2022 की दोनों पारियों में हुई वनरक्षक भर्ती परीक्षा-2020 का पेपर लीक होने की जानकारी होने पर एसओजी में मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में उप महानिरीक्षक पुलिस

एसओजी राजस्थान जयपुर परिस देशमुख के पर्यवेक्षण में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भवाना शंकर मीणा की ओर से गिरफ्तार शुदा आरोपियों की अपर जिला एवं सेशन न्यायालय बांसवाड़ा में सोमवार को आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल की गई।

भजनलाल शर्मा ने किए मां नर्मदा के दर्शन

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने गुजरात प्रवास के पहले दिन सोमवार को केवडिया में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा के साथ पावन नर्मदा नदी के तट पर स्थित मां नर्मदा केदेवीय स्वरूप के दर्शन कर पूजा-अर्चना की। शर्मा ने इस दौरान मां नर्मदा के प्रदेशवासियों का जीवन सुख-समृद्धि और खुशहाली से परिपूर्ण होने की कामना की।

आवास प्लस सर्वेक्षण की सूची में अब कोई भी प्रतीक्षारत परिवार शेष नहीं रहेगा

- केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में राजस्थान को 2 लाख 73 हजार 752 घरों का लक्ष्य आवंटित कर दिया है
- प्रदेश के ग्रामीण विकास विभाग ने भी जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर सभी पात्र परिवारों को स्वीकृति मय प्रथम किश्त जारी करने के निर्देश दे दिए हैं

रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) सहित अन्य योजनाओं का अधिकाधिक लाभ प्रदेश को दिलवाने के संबंध में सार्थक चर्चा की थी।

इस पर सरकारात्मक रुढ़ दिखाते हुए केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत राजस्थान को 2 लाख 73 हजार 752 घरों का

लक्ष्य आवंटित कर दिया है। इस तरह राज्य सरकार के प्रयासों से वर्ष 2018 के आवास प्लस सर्वेक्षण की सूची में अब कोई भी प्रतीक्षारत परिवार शेष नहीं रहेगा। इससे पहले राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत लगभग 22 लाख 23 हजार आवास बनाने के लक्ष्य का आवंटन किया गया था, जिनमें से करीब 20 लाख आवासों का काम लगभग पूरा हो चुका है। प्रदेश के ग्रामीण विकास विभाग ने भी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर

ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाज़ार एग्जीबिशन का उद्घाटन



ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार के दूसरे दिन सीतापुरा स्थित नोबोटेल् जयपुर कन्वेंशन सेंटर में ओडिशा की उपमुख्यमंत्री, प्रावती परिदा, भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव एवं पर्यटन महानिदेशक, सुमन बिल्ला और फिक्की की पूर्व अध्यक्ष एवं ललित सूरि हॉस्पिटैलिटी ग्रुप की सीएमडी, डॉ. ज्योत्सना सूरि ने एग्जीबिशन का उद्घाटन किया।

जयपुर। ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार (जीआईटीबी) के 14वें संस्करण के दूसरे दिन सीतापुरा स्थित नोबोटेल् जयपुर कन्वेंशन सेंटर में एग्जीबिशन की रिबन कटिंग सेरेमनी के साथ भव्य शुरुआत हुई। ओडिशा की उपमुख्यमंत्री, प्रावती परिदा; भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव एवं पर्यटन महानिदेशक, सुमन बिल्ला; आयोजन के अंतर्गत आवास की स्वास्थ्य एवं फिक्की की पूर्व अध्यक्ष एवं ललित सूरि हॉस्पिटैलिटी ग्रुप की सीएमडी, डॉ. ज्योत्सना सूरि ने एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। इस

पूरे दिन के दौरान बायर्स और सैलर्स के बीच पूर्व निर्धारित बी2बी बैठकों का सिलसिला उन्साहपूर्वक चला। इस इंटरनेशनल मार्ट का आयोजन पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) द्वारा किया जा रहा है। इस आयोजन को होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (एचआरएआर), इंडियन हेरिटेज होटल्स एसोसिएशन (आईएचएचए)

और राजस्थान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स (राटो) जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और क्षेत्रीय एसोसिएशंस का सहयोग प्राप्त है। इस आयोजन में 53 देशों से आए कुल 270 फीरन टूर ऑपरेटर्स (एफटीओ) और 10 राज्यों के पर्यटन बोर्ड प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। भाग लेने वाले राज्यों में राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, अंडमान और निकोबार, गुजरात, तमिलनाडु के साथ-साथ दिल्ली भी शामिल है।

